दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2001

भ्रष्ट चुनावी छात्र राजनीति के खिलाफ आम छात्रों का गुस्सा और विकल्प की बेचैनी

किसी मजबूत क्रान्तिकारी विकल्प के अभाव में पिछले सात सितम्बर को सम्पन्न दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2001 में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पदों पर कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एन.एस.यू.आई. और उपाध्यक्ष के पद पर संघ-भाजपा के छात्र संगठन के प्रत्याशी ने कब्जा जमा लिया। लेकिन विगत कई वर्षों की भाँति एक बार फिर आम छात्रों की भारी आबादी ने साफ तौर पर प्रकट कर दिया कि वे मौजूदा भ्रष्ट चुनावी छात्र राजनीति से बुरी तरह ऊब चुके हैं। इसके प्रति उनके मन में गुस्सा है और विकल्प के लिए बेचैनी भी।

पिछले चुनावों की तरह इस बार भी 'मनी पावर', 'मसल पावर' और 'फेस पावर' (ग्लैमर प्रदर्शन) के बूते चुनावी पार्टियों के पिछलग्गू छात्र संगठनों ने चुनाव लड़ा और हार-जीत का यह घिनौना खेल सम्पन्न हुआ। लेकिन उम्मीदवारों की जी-तोड़ कोशिशों के बावजूद कुल 35 फीसदी छात्रों ने ही वोट डाले। साफ है कि मौजूदा छात्र संघ को आम छात्रों की बहुसंख्या का मत और विश्वास ही नहीं प्राप्त है। बिल्कुल वही स्थिति जैसी आजकल लोकसभा-विधानसभा चुनावों में होती है। लेकिन इसके बावजूद ये छात्रों के रहनुमा होने का दम भरेंगे और छात्र संघ में बैठकर लम्बे संघर्षों के बाद हासिल छात्रों की इस प्रतिनिधि संस्था का अपने निहित स्वार्थों के लिए जमकर इस्तेमाल करेंगे।

दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सत्तर कालेजों के अपने छात्र संघ चुनावों में भी 'डूसू' (दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का संक्षिप्त नाम) चुनावों की तर्ज पर ही धनबल-शस्त्रबल और ग्लैमर का फूहड़ और नंगा प्रदर्शन हुआ। जाकिर हुसैन कालेज के एक प्रत्याशी की तो हत्या तक प्रतिद्वंद्वियों ने कर दी। श्यामलाल कालेज में डी.एस.यू. ने एक पद पर जीत हासिल की, लेकिन आम तौर पर कालेजों के चुनावों का नज़ारा भी वही था, जो 'डूसू' चुनावों का था।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में जनतांत्रिक प्रक्रिया की 'ट्रेनिंग' के नाम पर एम.पी.-एम.एल.ए. बनने की इस अश्लील ट्रेनिंग के बीच आम छात्रों की एक पहलकदमी भी बेहद महत्वपूर्ण रूप में उभरकर सामने आयी है, जिससे भविष्य के कुछ अच्छे संकेत मिलते हैं। दिशा छात्र संगठन नामक एक क्रान्तिकारी छात्र संगठन ने चुनाव में आम छात्रों के बीच एक व्यापक एवं सघन भ्रष्ट छात्र राजनीति विरोधी अभियान चलाया। व्यापक जनसम्पर्क, क्लासरूम, मीटिंगों, व्यापक पोस्टरिंग और पर्चा वितरण के जरिये आम छात्रों को एक क्रान्तिकारी विकल्प के लिए ललकारा। इस अभियान के जरिये आम छात्रों से यह आह्वान किया गया कि वे छात्र संघ के उम्मीदवारों से सवाल पूछें कि अपने मतदाताओं के भविष्य और कैम्पस के बाहर भटकते करोड़ों बेरोजगार नौजवानों के लिए संघर्ष की उनके पास क्या योजना है। इसी तरह के कई अन्य सवाल पूछने और इस स्थिति को बदलने के लिए आम छात्रों को उद्वेलित किया गया।

इस अभियान के तहत जारी पर्चे में यह विश्वास व्यक्त किया गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय और समूचे देश की छात्र राजनीति की मौजूदा स्थिति बदलकर रहेगी। क्योंकि 'हम एक ज़िन्दा कौम हैं और ज़िन्दा कौम के बहादुर युवा ज़िन्दा सवालों पर सोचते हैं। इसलिए कि 'अभी इस देश के युवाओं का विवेक मरा नहीं है, वीरता ज़िन्दा है, इंसाफ़पसन्दगी ज़िन्दा है!' इसलिए कि 'भारत के युवाओं के यौवन का पराक्रम ज़िन्दा है।'

'दिशा' के इस अभियान को आम छात्रों का व्यापक समर्थन मिला क्योंकि जो सवाल उठाये गये थे वे आम छात्रों के मन में पहले से ही उमड़-घुमड़ रहे थे और वे बेचैनी के साथ विकल्प भी तलाश रहे हैं। जब सवाल सही ढंग से उठा दिये जाते हैं तो जवाब तक पहुंचने में देर नहीं लगती। संकेत मिल चुका है कि आने वाले समय में आम छात्र मौजूदा पतित छात्र राजनीति का मुंहतोड़ जवाब देकर रहेंगे।

यह सही है कि छात्र संघ चुनाव में वोट न देने वाले बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो इस पूरे तमाशे से ऊबे और चिढ़े हुए हैं और छात्र संघ को, छात्र राजनीति को और पूरी राजनीति को ही गन्दी चीज़ मानने लगे हैं। लेकिन इन्हें भी देर-सवेर भगतसिंह की कही यह बात समझनी ही होगी कि अलग-थलग रहकर विद्यार्थी न तो खुद को बचा पायेंगे और न देश को – उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ राजनीति का भी ज्ञान हासिल करना होगा और वक्त आने पर मैदान में कूदना होगा। इसके साथ ही यह बात भी उन्हें समझनी होगी कि जब अच्छे, स्वाभिमानी और संवेदनशील युवा मैदान से हटे रहेंगे तो वह मैदान अपराधियों, चुनावी पार्टियों के टुटपुंजियों और धनिकपुत्रों की धमाचौकड़ी के लिए खाली ही रहेगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं तमाम कैम्पसों के छात्रों-युवाओं को यह सोचना ही होगा कि आज बेहद अहम सवाल हमारे सामने खड़े हैं। अन्धाधुन्ध छंटनी, तालाबन्दी का सिलसिला जारी है, रोजगार लगातार सिमटता-सिकुड़ता जा रहा है, दमन-उत्पीड़न-भ्रष्टाचार से देश कराह रहा है, देशी और विदेशी गिद्ध चारों ओर से इसे नोंच-चींथ रहे हैं। इस माहौल में आम जनता के बहादुर सपूतों के कन्धों पर वक्त ने जो अहम जिम्मेदारियां डाल दी है, उनके मुकाबले यह तो अदना-सा कार्यभार है कि वे छात्र संघ की राजनीति की कमान अपने हाथ में लें और उसे संघर्ष का जुझारू मंच बनाएं। कैम्पस के जनतांत्रीकरण और रोजगार और समान शिक्षा के अधिकार की लड़ाई तभी मजबूत हो सकेगी।

● प्रवीण